भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2255

जिसका उत्तर मंगलवार 31 जुलाई, 2018 को दिया जाना है

फेम इंडिया योजना

2255. कुँवर भारतेन्द्र सिंह:
श्री प्रह्लाद जोशी:
श्री राजीव प्रताप रूड़ी:
श्री आर पी मरुदराजा:
डॉ उदित राज:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फेम इंडिया योजना के चरण-1 ने अपने लक्ष्य को पूरी तरह पा लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना व्यय किया गया है तथा चरण-1 के अंतर्गत बिहार सहित राज्य-वार क्या लक्ष्य पूरे किए गए;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) फेम इंडिया योजना के चरण-2 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इस योजना को आरंभ करने की समय-सीमा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने विद्युत वाहनों के लिए समर्पित चार्जिंग स्टेशननों के द्वारा विश्वसनीय विद्युत की पहुंच प्रदान करने के लिए कोई रूपरेखा बनाई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ग): हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा इनकी सतत वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए भारी उद्योग विभाग ने दिनांक 1 अप्रैल, 2015 (चरण-1) से दो वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए एक योजना नामतः फेम इंडिया [भारत में इलेक्ट्रिक (और हाइब्रिड) वाहनों का विनिर्माण और तीव्र अंगीकरण] तैयार की जिसे आगे दिनांक 30 सितंबर, 2018 तक बढ़ा दिया गया है। इस स्कीम का उद्देश्य हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक वाहन बाजार विकास और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए इसके विनिर्माण पारिस्थितिक तंत्र की सहायता करना है।

स्कीम के बल दिए जाने वाले चार क्षेत्र हैं, अर्थात् प्रौद्योगिकी विकास, मांग सृजन, प्रायोगिक परियोजना और चार्जिंग अवसंरचना।

मांग प्रोत्साहनों के माध्यम से बाजार के सृजन का उद्देश्य सभी वाहन घटकों अर्थात दुपहिया, तिपहिया ऑटो, चोपहिया यात्री वाहनों, हल्के व्यावसायिक वाहनों और बसों को प्रोत्साहित करना है। व्यापक अंगीकरण को समर्थ बनाने के लिए अपफ्रंट कम खरीद मूल्य के रूप में क्रेताओं (अंतिम उपयोगकर्ता/उपभोक्ता) के लिए मांग प्रोत्साहन उपलब्ध है। दिनांक 1 अप्रैल, 2015 में स्कीम के आरंभ होने से अब तक बिहार सहित लगभग 2,18,759 इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों (एक्सईवी) को ₹253.48 करोड़(लगभग) के मांग प्रोत्साहनों के द्वारा सहायता दी गई है। इसके परिणामस्वरूप लगभग 30316917 लीटर ईंधन की बचत हुई और 75847082 कि.ग्रा कार्बन डाइ-ऑक्साइड में कमी आई है। इसके अलावा, अब तक इस स्कीम के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए 26 ओईएम के एक्सईवी के 102 मॉडल पंजीकृत किए गए हैं।

स्कीम के बल दिए जाने वाले विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत अनुदान देने के लिए सचिव (भारी उद्योग) की अध्यक्षता में परियोजना कार्यान्वयन एवं मंजूरी समिति (पीआईएससी) द्वारा प्रायोगिक परियोजनाओं, अनुसंधान एवं विकास/प्रौद्योगिकी विकास और सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना घटकों के अंतर्गत विशिष्ट परियोजनाएं भी अनुमोदित की जाती हैं।

इसके अलावा, सार्वजनिक परिवहन में ई-मोबिलिटी को और बढ़ावा देने के लिए विभाग ने एक मिलियन से अधिक की आबादी वाले शहरों और विशेष श्रेणी के राज्यों को इलेक्ट्रिक बसों, इलेक्ट्रिक चोपहिया यात्री कारों और इलेक्ट्रिक तिपहियों के संयोजन में मांग प्रोत्साहन देकर रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से इलेक्ट्रिक पावरट्रेन पर आधारित सार्वजनिक और साझा मोबिलिटी आरंभ करने की घोषणा की। इस ईओआई के माध्यम से 9 चुनिंदा शहरों को 455 इलेक्ट्रिक बसों के लिए प्रोत्साहन/अनुदान दिए जा रहे हैं।

फेम इंडिया स्कीम के चरण-1 के लिए बजटीय आबंटन एवं उपयोग (बिहार सहित) के ब्यौरे निम्नानुसार हैः-

क्र. सं.	**वित्तीय वर्ष**	**बजट आबंटन**	**निधि का उपयोग**
1.	2015-16	₹75 करोड़	₹75 करोड़
2.	2016-17	₹144 करोड़	₹144 करोड़
3.	2017-18	₹165 करोड़	₹165 करोड़
4.	2018-19 (30.06.2018 तक)	₹207 करोड़	₹23 करोड़ (लगभग)

(घ) और (ङ): फेम इंडिया स्कीम की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, इस स्कीम के चरण-1 में प्राप्त अनुभव और परिणाम के आधार पर स्कीम की उचित रूप से समीक्षा की जाएगी, जो मूल रूप से दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से दो वर्ष की अवधि के लिए थी। तथापि, स्कीम के चरण-1 को दिनांक 30 सितंबर, 2018 तक बढ़ा दिया गया है। फेम-II स्कीम को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

फेम स्कीम के अंतर्गत सरकार ने चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना से संबंधित कुछ परियोजनाएं अनुमोदित व मंजूर की हैं, जो निम्नानुसार हैः-

क्र.सं.	**परियोजना का नाम**	**प्रचालन एजेंसी का नाम**
1.	बैंगलुरु में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सार्वजनिक तीव्र चार्जिंग अवसंरचना नेटवर्क	लिथियम अर्बन टेक्नालॉजीज प्रा.लि. के सहयोग से मेसर्स महिंद्रा रिवा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रा.लि
2.	आरईआईएल, जयपुर द्वारा एनसीआर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सौर आधारित चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना हेतु प्रस्ताव	राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, (आरईआईएल), जयपुर
3.	बीएचईएल द्वारा उद्योग भवन परिसर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सौर आधारित चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना हेतु प्रस्ताव	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (बीएचईएल)
4.	आरईआईएल, जयपुर द्वारा 200 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव	राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, (आरईआईएल), जयपुर

****